have more oil and gas from West Bengal also.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, कच्चे तेल के आयात के लिए काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और उसके कारण इस विभाग को जागरूक होना चाहिए। कोलकाता के बारे में कहा गया है कि कोलकाता शहर गैस के ऊपर तैर रहा है। इतनी गैस और इतना आयल वहां पर है खास करके बंगाल की खाड़ी में। इसके पहले सारा जोर मुम्बई हाई या सदर्न स्टेट्स की तरफ दिया गया और पूर्व के क्षेत्र पर नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल निकाला गया है। पर हमारे ओएनजीसी के तहत जितने तेल के कुएं हैं वहां पर गैस और आयल का रेशियो दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह रेशियो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो तेल और कुएं बंद करने पड़ते हैं। हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि उसमें तेल के कुओं में बहुत ज्यादा गैस और आयल का रेशियो बढ़ गया है। अगर यह बढ़ जाने पर ये बंद होते हैं तो हमारे पास एकदम आयल क्राइसिस पैदा हो सकती है।

तो खास करके पूर्व क्षेत्र में, कोलकाता और बंगाल की खाड़ी में जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा कि कोशिश करेंगे पर उसकी प्रायमरी स्टडी है, उसका जो डाटा है वह आपको सैटेलाइट के माध्यम से मिलता है। आपको जो सैटेलाइट के माध्यम से डाटा मिला है उसको एनेलाइज़ करने के लिए, फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए कि इसमें कितना आयल निकलेगा, कितना एक्स्ट्रेक्ट कर सकेंगे, यह कराने के लिए जो आपकी प्रायमरी रिक्वायरमेंट है क्या वह रिक्वायरमेंट आपने पूर्व क्षेत्र के लिए पूरी की है या नहीं, यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री राम नाईक: यह बात सही है कि गैस की आवश्यकता सब जगह पर है। मान्यवर सदस्य ने कहा कि कोलकाता गैस पर तैर रहा है। गैस निकलेगी तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस समय पर मुझे लगता है कि कोलकाता गैस के लिए तरस रहा है। इस गैस के तरसने के कारण हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा निकालें और इसलिए जो भी सर्वे किए हैं उनके आधार पर हमने एनईएलपी के ब्लॉक्स में पश्चिम बंगाल के ब्लॉक्स इन्कलूड किए थे। इसलिए एनईएलपी-2 में एक आन-लैंड और एक आफ-शोर-दो ब्लॉक्स के लिए बिड्स आई हैं। जानकारी के आधार पर ही यह काम शुरू होता है। अब कहां ड्रिल करना है उसका दूसरा अभ्यास का तरीका होता है। उसके आधार पर यह काम शुरू होगा।

Weak Cooperative Banks

*23. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the most of the Cooperative Banks are weak;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have ascertained the causes of sickness of these Cooperative Banks;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether the norms of RBI are being flouted by most of the Cooperative Banks; and

(f) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per reports received from Reserve Bank of India (RBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), it is not correct to say that most of the cooperative Banks in the country are weak. Of the 2087 urban cooperative Banks in the country as on 31st October, 2001 only 262 are classified as weak, constituting 12.6% of the total number of urban cooperative Banks. Similarly, the statutory inspection of State Cooperative Banks (SCBs) and District Central Cooperative Banks (DCCBs) have revealed that as on 30th June, 2001, 7 SCBs out of 30 and 141 DCCBs out of 369 having negative networth can only be classifed as weak.

(c) and (d) A Task Force headed by Shri Jagdish Capoor constituted by Government to study the cooperative credit system has indicated that weakness in the cooperative credit structure is primarily due to dual control of RBI and State Governments, limited resources, dependence on higher financing agencies, lack of skilled manpower, viability problems and inadequate spread, extreme politicalisation/bureaucratic interference, rising cost and lack of professional management, etc.

(e) and (f) It is not correct to say that the norms/guidelines issued by RBI are flouted by most of the Banks. RBI/NABARD take appropriate action wherever any of these Banks are found to be not complying with the provisions of Banking Regulation Act or guidelines issued by them.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Keeping in view the primacy of the role of credit cooperatives and the need to review and improve the functioning of the credit cooperatives, various groups and committees have been constituted from time to time. In the recent past, three such groups/committees were formed.

A High-Power Committee was appointed by the Reserve Bank of India, a Task Force was appointed by the Government of India, and a Committee of Experts was also formed by NABARD. Their reports have been submitted in the last two years. The two main causes of sickness that these committees / groups brought out were: (i) low capital base; and (ii) inadequate loan appraisal system.

The reports state that the Banks succumb to the pressure of politicians or influential individuals.

Out of 2084 Urban Cooperative Banks that are presently operating in the country, 249 — about 12 per cent — have been listed as weak by the Reserve Bank of India.

In the year 2000-01, the Reserve Bank of India had withdrawn licences of 12 Cooperative Banks. The figure of failures in the current year, *i.e.* 2001-02 is likely to increase.

Part (a) of my question is: Has the Government been able to determine what amount will be for the capital base of the Cooperative Banks to be increased and what action the Government proposes to take towards that?

Part (b) of my question is: In order to make the cooperative credit system sustainable, to what extent has the Government been able to introduce professionalism in the operation of these institutions so that they are run on the basis of sound business principles and do not show favour under pressure from politicians or influential individuals.

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, माननीय सदस्य ने सही जिक्र किया है कि श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता वाली टॉस्क फोर्स ने काफी सुझाव दिए हैं। उसके बाद मुख्य मंत्री ने एक कांफ्रेंस भी की है। फिर एक छोटी कमेटी भी एप्वायंट की है जिसके कारण यह रिवाइटलाइजेशन की बात वहां चल रही है। आठ हजार करोड़ से ज्यादा उसके लिए चाहिए। इस महीने के आखिर तक वह रिपोर्ट भी आ जाएगी और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए काफी प्रावधान करने की कोशिश भी वह कमेटी कर रही है। दूसरी बात यह है कि वीक बैंक जो हैं, स्पेसेफिकली नागरिक सहकारी बैंक जिसको अर्बन कोआपरेटिव बैंक कहते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा है, तो वीक अर्बन कोआपरेटिव बैंकों की संख्या कम हो रही है तथा अगले साल संख्या और भी कम हो जाएगी। जो पुराना कैपिटल बेस था वह एक लाख था। अभी जो नए नॉर्म्स हैं उनमें एक लाख से कम जो आबादी है उसके लिए 25 लाख का नॉर्म है, शडयूल्ड कास्ट हो तो 1/3 और महिला बैंक हो तो 50 परसेंट का नॉर्म है। जो एक से पांच लाख है उसके लिए एक करोड़ का एंट्री प्वायंट है, 5 लाख से 10 लाख जहां है वहां दो करोड़ है और 10 लाख से ऊपर के लिए 4 करोड़ के एंट्री नॉर्म्स रखे गए हैं।

सरकार की यह कोशिश है कि जल्दी जल्दी से कपूर कमेटी का फैसला हो जाए और रीवाइटलाइजेशन ऑफ कोआपरेटिव मूवमेंट का कार्य, वह चाहे नागरिक अर्बन कोआपरेटिव बैंक हो या डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हो या स्टेट कोआपरेटिव बैंक हो या लैंड डिवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, उसमें सभी का जिक्र किया है। मेरे ख्याल से तफसील के साथ इस महीने के आखिर तक सारा काम पूरा हो जाएगा।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: I come to my second question. The effectiveness of the control of cooperative Banks have diminished due to the system of dual control of the urban cooperatives, *viz.* by the Reserve Bank of India and the State Governments.

It is reported that top officials of the Banks receive loans without extending collaterals. In the case of Krushi Bank, the Chairman and the Vice-Chairman got loans without collaterals and funds were siphoned off. In Madhavpura Bank, Ketan Pareekh was given Rs. 800 crores against all norms.

So, my question is: Has the Government explored the possibilities to establish a suitable unified agency to supervise the cooperative credit institutions which was one of the suggestions of the expert body?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सर, यह बात बिल्कुल सही है कि माधवपुरा बैंक के बाद जितने नागरिक सहकारी बैंक हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इंस्पैक्शन करने का काम हो रहा है और उसी में यह आन्ध्र कृषि बैंक है और 5-6 बैंक हैं, जिन्होंने अधूरा काम किया है और थोड़ा उनमें लोगों का नुकसान भी हुआ है।.....(**व्यवधान**) माधवपुरा में तो पूरा नुकसान हुआ है।...(**व्यवधान**) माधवपुरा की नहीं, लेकिन जो आंध्र की बैंक है, अभी कोई राज्य सरकार उसमें दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं है।

There are eight Banks now under the inspection of the RBI, which have been found to be sick. Some cases of frauds and mismanagement have been reported in the same report. The Government is fully aware of this and is thinking to have a different kind of monitoring system. As a regulatory authority, RBI has suggested some mechanism. The Government is considering those suggestions. Monitoring will be there. At the same time, professional management will be there. Moreover, for the purpose of de-politicalisation of the cooperative system as a whole, we are issuing credit cards to the borrowes. That way there will be no policical interference in the sanctioning of loans. At any point of time, no loan will be issued to the big borrowers, without security.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.